



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 828]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 13, 2001/कार्तिक 22, 1923

No. 828]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 13, 2001/KARTIKA 22, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2001

का. आ. 1124(अ).— यतः पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आमतौर पर पी.एल.ए. के नाम से जाना जाता है, और इसके राजनीतिक अंग, रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रन्ट (आर.पी.एफ.), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट (यू.एन.एल.एफ.), पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.) और इसके सशस्त्र अंग, "रेड आर्मी", कांगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.) और इसके सशस्त्र अंग जिन्हें "रेडआर्मी" भी कहा जाता है, कांगलेपाओल कानबा लुप (के.वाई.के.एल.) और मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रन्ट (एम.पी.एल.एफ.) (जिन्हें यहां इसके बाद सामूहिक रूप से मैतेई उग्रवादी संगठन कहा गया है) ने :

- (i) भारत से मणिपुर राज्य को अलग करके स्वतन्त्र मणिपुर बनाने के अपने लक्ष्य की खुले तौर पर घोषणा की है ;
- (ii) अपने उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं ;
- (iii) मणिपुर में सुरक्षा बलों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों और कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर हमले कर रहे हैं ;
- (iv) अपने संगठन के लिए धन एकत्र करने के लिए सिविलियन जनता को डराने-धमकाने, जबरन धन ऐंठने और लूटपाट के कार्य करते रहे हैं ; और
- (v) अपने अलगावादी उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयोजन से हथियारों और प्रशिक्षण के जरिए सहायता प्राप्त करके और जनमत को प्रभावित करने के लिए विदेशी स्रोतों से संपर्क स्थापित करने के प्रयास करते रहे हैं ;

2. और यतः, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उपर्युक्त कारणों से मैतेई उग्रवादी संगठन और उनके द्वारा स्थापित अन्य निकाय जिनमें ऊपर उल्लिखित सशस्त्र समूह भी शामिल हैं, विधिविरुद्ध संगठन हैं।

3. यतः अब, विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मैतेई उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आमतौर पर पी.एल.ए. के नाम से जाना जाता है और इसके राजनीतिक अंग, रेवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रन्ट, (आर.पी.एफ.), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट (यू.एन.एल.एफ.), पीपुल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.) और इसके सशस्त्र अंग, "रेड आर्मी", कांग्लेपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.) और इसके सशस्त्र अंग जिन्हें "रेड आर्मी" कहा जाता है, कांगले याओल लुप (के.वाई.के.एल.) और मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रन्ट (एम.पी.एल.एफ.) को गैर-कानूनी संगठन घोषित करती है।

4. और यतः-

- (i) मैतेई उग्रवादी संगठनों को सशस्त्र समूहों और सदस्यों द्वारा सुरक्षा बलों और सिविलियन जनता पर बार-बार लगातार हिंसात्मक और आक्रामक कार्रवाईयाँ जारी हैं;
- (ii) मैतेई उग्रवादी संगठनों की संख्या में वृद्धि हुई है;
- (iii) धन संग्रह / धन ऐंठने और अत्याधुनिक हथियारों को प्राप्त करना जारी है;
- (iv) शरणस्थल, प्रशिक्षण और चोरी छिपे हथियार और गोला बारूद प्राप्त करने हेतु पड़ोसी देशों में शिविर बरकरार रखे जा रहे हैं।

5. और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मैतेई उग्रवादी संगठनों की उक्त गतिविधियाँ भारत की संप्रभुता और अखण्डता के प्रति अहितकर हैं और यदि उनपर तुरंत अंकुश और नियंत्रण नहीं लगाया गया तो उक्त मैतेई उग्रवादी संगठन पुनः संगठित हो जाएंगे और हथियारों से लेस हो जाएंगे, अपने संवर्गों का विस्तार कर लेंगे, अत्याधुनिक हथियारों की प्रप्ति कर लेंगे, सिविलियनों और सुरक्षा बलों के जीवन को भारी क्षति पहुंचाएंगे और मणिपुर को भारत से अलग करने की अपनी गतिविधियाँ तेज कर देंगे।

6. अतः, अब, पैरा 4 और 5 में उल्लिखित परिस्थितियों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मैतेई उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आमतौर पर पी.एल.ए. के नाम से जाना जाता है और इसके राजनीतिक अंग रिबोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आर.पी.एफ.), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू.एन.एल.एफ.), पीपुल्स रिबोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.) और इसके सशस्त्र अंग "रेड आर्मी", कांग्लेपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.) और इसके सशस्त्र अंग जिन्हें भी "रेड आर्मी" कहा जाता है, कांगले याओल कन्बा लुप (के.वाई.के.एल.) और मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एम.पी.एल.एफ.) को तत्काल प्रभाव से गैर-कानूनी घोषित किया जाना अनिवार्य है; और तदनुसार, उक्त धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्ग किए जाने वाले किसी आदेश के अध्याधीन, सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं.8/22/2001-एन.ई.-1]

सुरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th November, 2001

S.O. 1124(E).— Whereas the People's Liberation Army, generally known as the PLA, and its political wing, the Revolutionary People's Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and the Manipur People's Liberation Front (MPLF) (hereinafter collectively referred to as the Meitei Extremist Organisations) have:

- (i) openly declared as their objective the formation of an independent Manipur by secession of Manipur State from India;
- (ii) been employing and engaging in armed means to achieve their aforesaid objective;
- (iii) been attacking the Security Forces, the Police, Government employees and law-abiding citizens in Manipur;
- (iv) been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their organisation; and
- (v) been making efforts to establish contacts with sources abroad for influencing public opinion and for securing their assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective.

2. And whereas, the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the Meitei Extremist Organisations and other bodies set up by them, including the armed groups named above, are unlawful associations.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Meitei Extremist Organisations, namely, the Peoples' Liberation Army, generally known as the PLA and its political wing, the Revolutionary People's Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and the Manipur People's Liberation Front (MPLF) to be unlawful associations.

4. And whereas, -

- (i) there have been repeated continuing and ongoing acts of violence and attacks by (armed groups and members of the Meitei Extremist Organisations) on the Security Forces and the civilian population;
- (ii) there has been an increase in the strength of the Meitei Extremist Organisations;
- (iii) there has been continued collection of funds/extortions and acquisition of sophisticated weapons;
- (iv) camps in some neighbouring countries continue to be maintained for the purpose of sanctuary, training and clandestine procurement of arms and ammunition.

5. And whereas, the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the Meitei Extremist Organisations are detrimental to the sovereignty and integrity of India, and if these are not immediately curbed and controlled, the said Meitei Extremist Organisations would regroup and rearm themselves, expand their cadres, procure sophisticated weapons, cause heavy loss of lives of civilians and Security Forces, and accelerate their activities aimed at secession of Manipur from India.

6. Now, therefore, having regard to the circumstances referred in paragraph 4 and 5, the Central Government is of the opinion that it is necessary to declare the Meitei Extremist Organisations, namely, the People's Liberation Army, generally known as the PLA, and its political wing, the Revolutionary People's Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and the Manipur People's Liberation Front (MPLF), as unlawful associations with immediate effect; and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of the said section 3, the Central Government hereby directs that the Notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 8/22/2001-NE. I]

SURENDRA KUMAR, Jt. Secy.